

ਰਿਮਾਟਤੇ ਪਾਕਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਤਜਾਗਾ ਹੋਣੀ ਫਰਦੂਤੇ



फर्स की ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा दौव खेलते हुए 88 आतंकवादियों की लिस्ट जारी कर दी है। इन पर दिखावटी कड़े प्रतिबंद लगा दिये हो लेकिन उसने विश्व के सामने 27 सालों से लगाए जा भारत के मोस्ट वाटेण्ड दाऊद के पाकिस्तान में होने तथा उसके कॉर्गाची में तीन आवास होने छापाये जा रहा झूट का स्वयं उजागर कर दिया है। भले ही एफएसीएफ की बैठक को अभी कुछ समय है लेकिन इतन तय है कि अगर उस बैठक में पाकिस्तान के कारनामों पर कार्रवाई की गई और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया तो चीन की शरण के बावजूद पाकिस्तान को नेस्तानबूद होने से कोई बचा नहीं पाएगा।

मुल्क पाकिस्तान को अगर दुनिया खुद को प्रासारिक बनाए रखेने वे लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना पर रहा है, तो कोई आश्रय नहीं। अगर दुनिया में अलग-थलग पड़ने लगता है, तो इसके बाद पाकिस्तान अब चीन को साथ रखने के लिए और भी मजबूर है। पाकिस्तान की जो आक्रामक अतार्किक नीतियां हैं, उनके मुताबिक

काइ भा समझदार, न्यायपूर्ण खुलकर उसके साथ खड़ा नहीं सकता। यह विडंबना है पाकिस्तान को भाग-भागकर चीन के पास जाना पड़ता है, जिसके अधार पर कभी पाकिस्तान बना था। जहां नमाज पढ़ने और दरखने पर भी पालंदी लगाई सकती है, वहां पाकिस्तान को विरूप में होना चाहिए? शायद इस पाकिस्तान में कम ही लोग विकरते हैं। वहां का सत्ता प्रतिष्ठान इतनी गहराई तक भारत विरोधी चुका है कि अपने देश की पहचान आदर्श और संपदा की कीमत चीन से दोस्ती खरीदना चाहता यह बदलाव उसके भटकाव को साबित करता है। जिन मुसिलिम मुल्कों को वह अपना सहोदर मान रहा, सऊदी अरब व संयुक्त अमीरात, उनकी बेरुखी पाकिस्तान को सुधार के लिए प्रेरणा नहीं कर पाई। पाकिस्तान समझ रखा रहा है कि भारत का वज्रजट पिछले कुछ दशकों में खुद मुस्लिम मुल्कों में किस कदर मजबूत हो चुका तो दूसरी ओर, इन्हीं दशकों पाकिस्तान का वज्रजट किया

समटता जा रहा हाथूरा दुनिया आतंकवाद फैलाने वाला कुछ्यात आतंकवादियों को शरण वाला पाकिस्तान एक बार पिछ दुनिया के सामने बेनकाब हो पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उसके यहां छिपा हुआ है और अगले दिन पाकिस्तान का मंत्रालय अपनी बात से मुकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। आतंकवादी तैयार करने वाला पाकिस्तान एक बार पिछ अपने चरित्र के लिए दुनिया में शाही हुआ है। पाकिस्तान ने ये स्वीकृति किया है कि दाऊद इब्राहिम उसने अब अपनी बात बदल देना पाकिस्तान को डर है कि भारत लिए मोस्टवार्टेड आतंकी को अपनी पर शरण देने बहुत खतरा साबित हो सकता है। अभी कुछ पूर्व कश्मीर को लेकर अपने उत्साह के कारण पाकिस्तान गहरी मुसीबत में फँस चुका सऊदी अरब ने उसके साथ कर्ज और तेल सप्लाई का समर्थन दिया है। इस बजते

पाकिस्तान का न कवल। डॉलर की तुरंत अदायगी करने वाले बल्कि उधार में तेल की आपूर्ति होने से उसके सामने अचानक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नाजायज हरकतों के कारण वैष्णव पाकिस्तान अरब देशों से अलग हो चुका है। बुनियादी हकीकत भुला देने वाले मुल्क पाकिस्तान अगर दुनिया में खुद को प्राप्त बनाए रखने के लिए एड़ी-चोड़ी जोर लगाना पड़ रहा है, तो आश्र्य नहीं। अरब दुनिया में उत्तरगढ़ लगाए लगा पाकिस्तान चीन को साथ रखने के लिए उत्तरगढ़ मजबूर है। पाकिस्तान कर्तव्य आक्रामक व अतार्किक नीति उनके मुताबिक कोई भी समर्पण न्यायपूर्ण देश खुलकर उसके खड़ा नहीं हो सकता। यह विंडो कि पाकिस्तान को भाग-भागकर चीन के पास जाना पड़ता है, उस धर्म की कर्तव्य परवाह न जिसके आधार पर कभी पावित्र बना था। जहां नमाज पढ़ने और रखने पर भी पाबंदी लगा सकती है, वहां पाकिस्तान को रूप में होना चाहिए? शायद इस पाकिस्तान में कम ही लोग

करत हा वहा का सत्ता प्राप्तान
इतनी गहराई तक भारत विरोधी हो
चुका है कि अपने देश की पहचान,
आदर्श और संपदा की कीमत पर
चीन से दोस्ती खरीदना चाहता है।
यह बदलाव उसके भटकाव को ही
साबित करता है। जिन मुस्लिम
मुल्कों को वह अपना सहोदर मानता
था, सऊदी अरब व संयुक्त अरब
अमीरात, उनकी बेरुखी भी
पाकिस्तान को सुधार के लिए प्रेरित
नहीं कर पाई। पाकिस्तान समझ नहीं
पा रहा है कि भारत का वजूद पिछले
कुछ दशकों में खुद मुस्लिम मुल्कों
में किस कदर मजबूत हो चुका है,
तो दूसरी ओर, इन्हीं दशकों में
पाकिस्तान का वजूद कितना
सिमटता जा रहा है। एक समय था,
जब अरब दुनिया में पाकिस्तान की
थोड़ी-बहुत सुनी जाती थी, लेकिन
विगत चार वर्षों में भारत की व्यापक
नीतियां अरब मुल्कों को समझ में
आने लगी हैं। इसके अलावा जो धर्म
के नाम पर चीन में हो रहा है, वह
भी अरब मुल्कों से छिपा हुआ नहीं
है। पाकिस्तान इस पर कोई चर्चा नहीं
करना चाहता, पर एक समय
आएगा, जब यह बात कहीं न कहीं
से उठेगी और तब सबसे ज्यादा
तकलिफ पाकिस्तान का होगा।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपने सेना
प्रमुख के अरब से लौटे ही चीन
पहुंच गए हैं, जहां उनकी चीनी
विदेश मंत्री से बात होगी। वहां भले
ही यह कहा जा रहा हो कि भारत की
कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन यह
बात अब छिपी नहीं है कि कश्मीर
और भारत विरोधी प्रस्तावों को
लेकर संयुक्त राष्ट्र में चीन क्यों
सक्रिय नजर आता है। संकेत साफ़
है, चीन और पाकिस्तान की
बातचीत का एक मुख्य मुद्दा भारत
ही है। खुद को आर्थिक रूप से
गिरवी रखते हुए पाकिस्तान जिस
तरह से भारत विरोधी सौदे-साजिशें
करता आ रहा है, उसे समझना किसी
के लिए भी मुश्किल नहीं है। कहना
न होगा, भारत को चिंता की नहीं,
सावधान रहने की जरूरत है।
पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी
गलत नीतियों के कारण अकेला पड़े
रहा है, साजिश हो या विलाप, चीन
उसका आखिरी कंधा है। भारत की
रणनीति सही है, जो भी देश
लोकतंत्र, न्याय, पारदर्शिता, अमन-
चौन और सद्द्वाव के दुश्मन हैं, हिंसा
और आतंक के प्रेमी हैं, उहें अकेले
बैठना ही पड़ेगा।

સમાદ્વાય

તત્ત્વે તત્ત્વે તો તત્ત્વા

जीतेंगे हम

किया गया था, और अब तक बत आठ महाना में दश-दुनिया में इसके कई हॉटस्पॉट बन गए हैं। चीन से निकलकर यह वायरस यूरोप पहुंचा, और अब एशियाई देशों में इसका संक्रमण शीर्ष पर पहुंचता दिख रहा है। भारत इससे खासतौर से प्रभावित है। रोजाना नए मामलों के लिहाज से हम सबसे ऊपर तो हैं ही, संक्रमित मरीजों की संख्या के हिसाब से भी हम शीर्ष देशों में शामिल हैं। हालांकि, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और रिकवरी रेट 70 फीसदी से अधिक हो चुकी है। वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण भी बस शुरू होने वाला है। तो क्या कोरोना वायरस के दिन जल्द ही लदने वाले हैं? इसका जवाब तलाशने से पहले यह जानना जरूरी है कि अब तक हमने इसका किस तरह मुकाबला किया है? अपने यहां मई तक संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। कहा जाता है कि लॉकडाउन के खुलने के बाद मामले तेजी से बढ़ने लगे। हालांकि, यहां मृत्यु-दर हमेशा से कम रही है। शुरुआती दिनों में यह बेशक पांच फीसदी के आसपास थी, लेकिन अब यह घटकर दो प्रतिशत से भी नीचे आ गई है। इसकी तुलना अगर टीबी से मरने वाले मरीजों या बाल मृत्यु-दर से करते हैं, तो काफी उमीदें बंधती हैं। टीबी से होने वाली कुल वैश्विक मौत की दो-तिहाई अंकेले अपने यहां होती है, जबकि बाल मृत्यु-दर में भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस में मृत्यु-दर सामान्य वायरस जैसी ही है। तब क्यों इसको लेकर पूरे देश में यूं अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया? दरअसल, दो बजहों से इस वायरस को लेकर डर फैला। एक, संक्रमित करने की इसकी तेज क्षमता और दूसरी, हमारे यहां स्वास्थ्य-सेवाओं की खस्ता हालत। बेशक, संक्रमित करने की इसकी ताकत दूसरे वायरसों से ज्यादा है, लेकिन आम लोग में डर का सबसे बड़ा कारण रहा, हमारा दरकता स्वास्थ्य ढांचा। आज भी भारत में कुल जीडीपी का 1.17 फीसदी हिस्सा ही स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी पर खर्च किया जाता है। नरीजतन, कोरोना संक्रमण का प्रसार होते ही अस्पताल मरीजों के बढ़ते बोझ से चरमाने लगे। यह स्थिति अब तक सुधरती नहीं दिख रही, जबकि हर वायरल संक्रमण का अपना चक्र होता है और संक्रमण के शिकार हरेक मरीज को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां कहने का आशय यह है कि कोरोना वायरस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। बेशक हमें इससे मजबूती से लड़ना है, लेकिन डर का बनता माहौल खतरनाक है। जरूरत आम लोगों में विश्वास बढ़ाने की है, लेकिन भरोसा जगना तो दूर, सरकार के राहत उपायों से खोफ ही अधिक बढ़ता दिखा। मसलन, ऐसी खबरें आईं कि गुणवत्ता पूर्ण पीपीई किट (निजी सुरक्षा उपकरण) वरिष्ठ डॉक्टरों को दिए गए, जबकि जूनियर डॉक्टरों या अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता के उपकरण मिले। उनके काम के घंटों को लेकर भी सवाल उत्तर ब्योर्किंग इस किट को

अनुच्छेद 370 कभी हट भी सकता है, यह कल्पनातीत हो गया था। ऐसे कोई प्रस्ताव दो दिन में संसद दोनों सदनों से दो तिरहाई बहुमत पारित हो सकता है, यह तो असंभव ही था। लेकिन पांच अगस्त, 2019 को यह असंभव इतनी तेजी संभव हुआ कि विरोधियों संभलने का मौका ही नहीं मिला। देखने के बाद भी चीन के राष्ट्रपति कोई सबक नहीं सुखा। तेह-लद्धन में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चढ़ाने से बचने की कोशिश सेना वहां तक आ गई, जहां उसे नहीं आना चाहिए था। शी चिनफिंग अपने ही देश के दार्शनिक की संतुष्टि को नजरअंदाज किया। शुन जू का दूसरा सूत्र है कि खुद उसके साथ अपने दुश्मन को समझ लाना सौ लड़ाइयां भी नहीं हरारेगे। पहले चिनफिंग यह भूल गए कि मैं चौकते हैं। पिछले 73 सालों से चीन एसी हारकतें करता रहा है, पर भारत ने कभी (1962 के युद्ध औड़कर) अपनी सेना का विजय जमावडा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नहीं किया। डोकलाम के समय भारत ने ऐसा नहीं किया था। चीन इसी मुगालते में था कि इस बार वैसा ही होगा। भारतीय सेना तैनाती ऐसी है, जैसी पूरी युद्ध तैयारी होनी चाहिए। यह चीन दूसरी गलती थी। वह अपने दुश्मन को यानी भारत को समझ नहीं पाया। जून ने कहा था कि अगर अपने जानते हो और अपने दुश्मन को जानते हो तो लड़ाई बराबरी पर छूटेगी। दोनों को नहीं समझे तो हार तय हो गलवन में भारतीय फैज ने जिस तरह चीन को जबाब दिया, उससे सारा देश कि उसने अपने पैज़ियों की क्षमता

समझने में भूल की।
चीन को अचरज का सामना वे सीमा पर ही नहीं करना। आर्थिक मोर्चे पर भी उसे भौमिका होना पड़ा। चीन से आयात पर ही निर्भरता और व्यापार के परिमाण देखते हुए वह निश्चित था कि एक को मजबून व्यापार के मोर्चे यथास्थिति बनाए रखनी पड़े। चीनी एस पर प्रतिबंध से कंपनियों पर एक के बाद एक का सिलसिला अभी रुका नहीं। इमेक इन इंडिया देश के लिए शआत्मनिर्भर भारत उसी का विकास है, पर मेक पॉर्ट वर्ल्ड की नीति ऐलान चीन का यह गुरुर तोड़ा लिए है कि वह दुनिया मैन्युफ्क्रिंग हब है। प्रधानमंत्री दुनिया के देशों को कहा कि अब भारत में निवेश कीजिए। हमारे जनतंत्र है और हम ज्यादा भरोसा

हैं। निशाने पर चीन ही है। शुन तीसरा मंत्र है सकात् तत्वोंधकारकों को साथ रखो। सरहद पर और आर्थिक क्षेत्र में पर दबाव बनाने तक ही सीमित रहा। अमेरिका आज खुले तो साथ है तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी के देशों साधने में मोदी की कूटनीति रही है। रूस जो पिछले कुछ से चीन के करीब आ गया था, भारत के प्रभाव में चीन को 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपूर्ति रोक दी, पर भारत व समय पर देने का वादा किया ने भारत का नाम लिए बिना कि हमें पता है कि यह किस दबाव में किया गया है। भारत कूटनीतिक प्रयासों और चीनियों विस्तारवादी नीति ने दुनिया के देशों को चीन के खिलाफ किया

मादा का रणनीत समझन में नाकाम विराधा



शहर का विगड़ता सूचना

नामा, जब नाउंडेन सोलिल तक पहुंचना चाहता था। सउंगा का नेटु संक्रमण की जानकारी नहीं दी जाती, बल्कि इससे ठीक होने वाले लोगों का जिक्र भी किया जाता है। यह एक अच्छी नीति है। इससे लोगों में भरोसा जगने लगा है कि कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं, जो सिर्फ उनकी जान ले। इसके मरीज ठीक भी हो सकते हैं। छोंकने या खासंते वक्त मुँह ढकने और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखने जैसे निर्देशों को भी लोगों के सामने इसी तरह पेश करना चाहिए, ताकि उनका डर कम हो। वैसे भी, इस तरह के व्यवहार आमतौर पर बचपन में ही हमें सीखा थिए जाते हैं। हां, अब इस पर गंभीरता से अमल करने की जरूरत है। अनिश्चितता के माहौल को खत्म करना भी जरूरी है। जैसे, एक निजी अध्ययन में मैंने पाया कि कोरोना-हेल्पलाइन नंबर बमुश्किल से काम करते हैं। अच्छल तो यह नंबर उठाना नहीं, और अगर कोई उठाता भी है, तो उचित सलाह देने का भरोसा देकर फोन रख देता है। इसी तरह, कुछ राज्य सरकारों ने ऐसी वेबसाइट लॉन्च की, जहां अस्पतालों के खाली बेड की जानकारी ली जा सकती है, लेकिन मुश्किल यह है कि जब तक सूचनाएं वेबसाइट पर दर्ज होती हैं, तस्वीर बदल चुकी होती है, यानी वेबसाइट पर तो अस्पतालों में खाली बेड दिखते हैं, पर असलियत में वे भर चुके होते हैं। इन सबसे भविष्य को लेकर लोगों के मन में कई दुश्मिताएं पनपी। वेशक समस्याएं हैं, पर उनके हल की तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत है, न कि मुश्किलों को और गहरा बनाने की। अपने यहां जनवरी के अंत में पहला मामला सामने आया था। बीते छह महीने से अधिक का वक्त गुजर गया है, लेकिन हम यह तय नहीं कर सके कि वायरस किस रूप में आगे बढ़ेगा? हॉटस्पॉट पर ही इसके संक्रमण को रोकने की दरकार थी, जिसमें हम सफल नहीं हो सके। इसीलिए चुनौती अब कहीं ज्यादा गहरी हो गई है। बहरहाल, उम्मीद बनी हुई है। कोरोना से जंग हम जीत सकते हैं। इसका चरित्र आम वायरस से बहुत अलग नहीं है, इसलिए इसे लेकर नीतियां भी उसी अनुरूप बननी चाहिए। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश उन तबकों के हित में ज्यादा हों, जिन्हें अपना पेट पालने के लिए गेजाना घर से बाहर निकलना पड़ता है।

अथव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा पांच-सात प्रतिशत अधिक नहीं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केवल कृषि पर आधारित होने का कारण उसकी अपनी सीमाएँ हैं। सीमाओं को समझा जाना चाहिए क्योंकि भारत सरीखे देशों में वह पर निर्भर आबादी की संख्या बढ़ अधिक है। अपने देश में बरसात के दिनों शहरों के आधारभूत ढांचे की पूरी तरह खुल जाती है। शायद कोई शहर हो जो बारिश के बाद जलभराव और गंदगी से पटाका दिखता हो। शहरी ढांचे के जल देहों का एक प्रमुख कारण यह है उनके विकास प्राधिकरण और निगम दूरगामी दृष्टि रखते आधारभूत ढांचे का निर्माण कर और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने नाकाम है। अक्सर शहरों में न बना आधारभूत ढांचा पांच-साल बाद ही बढ़ती जनसंख्या कारण नाकापी लगने लगता आखिर इसका क्या मतलब कि 10-15 साल बाद आधारभूत देश के निर्माण में धन व्यय करना पड़े।

यह सिलासला कभी खत्म होता, क्योंकि कुछ न कुछ बनता रहता है। चूँकि जो गांव और ग्राम क्षेत्र शहरों का हिस्सा बन जाते वहां के आधारभूत ढांचे को सुधारना की कोई पहल नहीं की जा सकती। इसलिए वहां अनियंत्रित निर्माण रहता है। इन गांवों की अधिकता और गैर-अधिग्रहीत जमीनों के बेतरतीब निर्माण कार्य भी जाहेर हैं और अतिक्रमण एवं अपनी चपेट में लेकर उसे करने लगता है। ऐसे इलाके अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, प्रदूषण जूझने लगते हैं। धीरे-धीरे बामारियां फैलाने की जड़ बन जाती हैं। कोविड महामारी के दौरान सामने आया कि अत्यधिक आबादी वाले इलाकों में केवल वायरस का संक्रमण कहीं तेज़ फैला। गांवों से पलायन करके वाले अधिकांश कामगार शहर गांवों या ऐसे उनके आसपास

विकास से जुड़ा एजेंसिया होती हैं और न ही राज्य से उत्तरे राजनीतिक संरक्षण के इन क्षेत्रों में होने वाले अनिमाण पर कोई रोक भी नहीं रह नहीं जाय यह होता है कि ऐसे रहने लायक नहीं रह जाते। हे यह चाहिए कि चाहे अधिकृत हों या अनधिकृत, उनमें लगभग समान मापदंड से विकास चाहिए। इससे किसी एक धर्म जरूरत से ज्यादा आबादी बसाहट को रोका जा सके शहरों के नियोजित विकास के जिन शहरी निकायों पर है सक्षम और जवाबदेह बनाने में सरकारों के अलावा सभासदों, और विधायकों की भी जिम्मेदारी लेकिन इस मामले में उनका योग्य मुश्किल से देखने को मिल इसी कारण शहरी निकाय अवृद्धि एवं भ्रष्टाचार के अड्डे बनकर रहते हैं। इन निकायों में जनता का ही कोई काम बिना लेन-देन हो। वैध काम के लिए भी रिश्ता पड़ती है। सभासद से लेकर और विधायक तक इस भ्रष्टाचार से बचने के लिए यहाँ आये हैं।

